पीपीपी मोड पर संचालित किए जाएंगे पर्यटक आवास गृह

राज्य, जागरण● लखनऊ : कैबिनेट की बैठक में पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी (सार्वजनिक निजी सहभागिता) मोड पर सौंपे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पर्यटन विभाग की तरफ से घाटे में चल रहे राही पर्यटक आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके चलते पहले भी कई राही आवास गृहों को पीपीपी मोड पर संचालित किए जाने के लिए निजी कंपनियों को सौंपा जा चुका है। इसी सिलसिले में इटावा स्थित सुमेर सिंह किला, कपिलवस्तु, शिकोहाबाद, मीरजापुर, मऊ स्थित झील महल रेस्टोरेंट, गोपीगंज, बस्ती व वृंदावन स्थित राही आवास गृहों को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने वित्तीय निविदा आमंत्रित कर कंपनियों का चयन कर लिया है।

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राचीन धरोहरों तथा विरासत भवनों को पीपीपी माडल पर विकसित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना पर पर्यटन विभाग पहले से ही काम कर रहा है। अब इसके लिए पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय परियोजना समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। समिति में अवस्थापना एवं

कैबिनेट के फैसले

- हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के लिए गठित होगी परियोजना समिति
- पर्यटन विभाग ने प्रदेश की 13 धरोहरों को किया है चिह्नित

औद्योगिक विकास विभाग, नियोजन व न्याय विभाग के प्रमुख सचिव या उनके द्वारा नामित अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग के महानिदेशक को सदस्य सचिव, जिलाधिकारी के अलावा संस्कृति, पर्यटन व पुरातत्व विभाग के निदेशक समिति के सदस्य होंगे। पर्यटन विभाग ने योजना के तहत ललितपुर स्थित बालबेहट किला, झांसी का टहरौली किला व रघुनाथ राव महल, मथुरा का सीताराम महल, गोंडा में स्थित वजीरगंज की बारादरी, लखनऊ स्थित आलमबाग भवन व कोठी गुलिस्तान ए-इरम, कानपुर स्थित टिकैतराय बारादरी, महोबा के मस्तानी महल व लेक पैलेस तालकोठी चरखारी तथा सेनापति महल, बांदा स्थित भूरागढ़ किला व रनगढ़ किला को पीपीपी मोड पर हेरीटेज पर्यटन के लिए विकसित करने को लिए चिह्नित किया है।

यह और उप्र की अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें

विधानमंडल सत्र का होगा एक ही चरण

राज्य, जागरण● लखनऊ : सूत्रों के अनुसार पहले सरकार संसद की तर्ज पर दो चरणों में विधानमंडल का बजट सत्र चलाने की तैयारी में थी किंतु अब एक बार में ही सत्र चलाने की बात है।

सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 का मूल बजट 7,36,437.71 करोड़ रुपये का पेश किया था। इसके बाद दो अनुपूरक बजट आ चुके हैं। जुलाई में पहला अनुपूरक बजट 12,209.93 करोड़ रुपये का आया था जबकि दूसरा अनुपूरक बजट दिसंबर में 17,865.72 करोड़ रुपये का था। दोनों अनुपूरक बजट मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष का कुल बजट 7,66,513.36 करोड़ रुपये हो गया है। ऐसे में सरकार इस बजट से बड़ा बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश करेगी।

सरकार का विशेष ध्यान प्रदेश में सड़कों का जाल और एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश का बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर रहेगा। बजट में नई परियोजनाओं और बिजली वितरण में सुधार के लिए बड़ी रकम आवंटित होने का अनुमान है। किसानों को राहत देने और कृषि क्षेत्र में नई योजनाओं के लिए भी सरकार दरियादिली दिखा सकती है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुधारने के लिए तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी बजट का बड़ा हिस्सा इन योजनाओं के लिए रखेगी।

बजट की तैयारियों में जुटी सरकार

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के बजट को अंतिम रूप देने में वित्त विभाग जुटा हुआ है। माना जा रहा है कि बजट का आकार करीब आठ लाख करोड़ रुपये होगा। बजट की तैयारियों के मद्देनजर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इस समय लगातार बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बजट पर लंबी बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभागों से बजट के संबंध में जो भी प्रस्ताव आए हैं, उनमें यदि कोई संशोधन है तो उसे करते हुए जल्द से जल्द बजट प्रस्तावों को तैयार कर लिया जाए। बजट को अंतिम रूप देने से पहले वित्त विभाग मुख्यमंत्री से मागदर्शन लेगा। मुख्यमंत्री के साथ बैठक अगले तीन से चार दिनों के अंदर हो सकती है।